

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 21 सितम्बर, 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल/जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल की ढालवाला सीवरेज योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 439/उन्तीस(2)/05-2(07पे0)/04 दिनांक 06 सितम्बर 2005 एवं शासनादेश संख्या 1948/उन्तीस(2)/07-2(114पे0)/07 दिनांक 28 सितम्बर 2007 एवं आपके कार्यालय पत्र संख्या 1123/नियोजन अनुभाग/धनावंटन प्रस्ताव /56 दिनांक 25.05.10 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल/जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल की निमार्णाधीन ढालवाला सीवरेज योजना हेतु रु० 100.00 लाख (रु० एक करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.12.2010 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

3- कराये जाने वाले कार्यों पर वित्त(वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

4- व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन कड़ाई से किया जाय।

5- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

7- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार संक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

8- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार संक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9- उक्त योजनाओं से सम्बन्धित स्वीकृत पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तें यथावत रहेंगी।





- 10- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- 11- यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हों, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।
- 12- मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV- 219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय/कार्य करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- 13- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के लेखानुदान सं०-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-आयोजनागत-101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-05- नगरीय पेयजल-01-नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान-20-सहायक अनुदान/ अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा।
- 14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 431/XXVII(2)/2010, दिनांक 16 सितम्बर 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

पृ० सं० 11740/उन्तीस(2)/10-2(07पे०)/2005तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
6. निदेशक, स्वजल परियोजना, देहरादून उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा० पेयजल मंत्री को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 10- निजी सचिव-सचिव पेयजल को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
11. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
13. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव